ई-न्यूज
24 न्यूज अपडेट
WebSite.: https://24newsupdate.in
उदयपुर, मंगलवार 15 अप्रैल 2025
Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com
वर्ष 2 अंक 25

अमरनाथ यात्रा- रजिस्ट्रेशन आज से शुरूः600 से ज्यादा बैंकों में ऑफलाइन फॉर्म मिलेंगे; बालटाल-पहलगाम रूट पर 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा

अमरनाथ यात्रा-2025 के लिए रजिस्ट्रेशन आज (15 अप्रैल) से शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 220 रुपए रखी गई है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 600 से ज्यादा बैंकों में किया जा सकता है।

इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त (रक्षाबंधन) तक (39 दिन) चलेगी। यात्रा दो रूट- पहलगाम (अनंतनाग) और बालटाल (गांदरबल) से होगी। लगभग 6 लाख श्रद्धालु यात्रा पर आ सकते हैं। 5 मार्च को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (SASB) की 48वीं बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा की तारीखों की घोषणा की थी। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर करने के कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। श्राइन बोर्ड ने e-KYC, RFID कार्ड, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और दूसरी व्यवस्थाओं को भी बेहतर करने का निर्णय लिया है, ताकि यात्रा अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित हो सके। बोर्ड का कहना है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा श्रद्धालु आ सकते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए जम्मू, श्रीनगर, बालटाल, पहलगाम, नुनवान और पंथा चौक पर रुकने और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की जा रही है।

श्रद्धालु बोले- यात्रा के लिए उत्साहित

श्रद्धालु रोहित ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के दौरान हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूं, यह मेरी दूसरी अमरनाथ यात्रा है। सभी यात्रियों का हेल्थ चेकअप अनिवार्य है। वहीं, श्रद्धालु सोनिया मेहरा ने कहा- यह मेरी दूसरी यात्रा है, मैं चाहती हूं कि हर साल इस पवित्र यात्रा पर जा सकूं।

2024 में लगातार दूसरे साल श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। 2023 में 4.5 लाख और 2024 में 5 लाख तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। साल 2012 में रिकॉर्ड 6.35 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए थे। 2022 में कोविड के कारण आंकड़ा घटा था और 3 लाख तीर्थयात्रियों दर्शन के लिए पहुंचे थे।

अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकीःतमिलनाडु से ई-मेल आया, लिखा- बढ़ा लो मंदिर की सुरक्षा

अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 14 अप्रैल (सोमवार) की रात राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक ई-मेल आया था। इसमें लिखा है- बढ़ा लो मंदिर की सुरक्षा। ट्रस्ट के अकाउंट अफसर महेश कुमार ने मंगलवार को पुलिस की साइबर सेल में केस दर्ज कराया है। धमकी मिलने के बाद जन्मभूमि परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली को एक्टिव किया गया है। पुलिस ने मंदिर के पास सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं, बाराबंकी, चंदौली और अलीगढ़ समेत कई जिलों के जिलाधिकारियों को भी धमकी भरा ई-मेल आया है। इसमें DM ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये सभी मेल तमिलनाडु से भेजे गए हैं।

मौसम विभाग ने जारी किया मानसून अपडेटःखेती के लिए अच्छी खबर, सामान्य से बेहतर मानसून; 105% बारिश की उम्मीद, अल नीनो का खतरा नहीं

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को बताया कि इस बार जून से सितंबर तक मानसून सामान्य से बेहतर रहेगा। मौसम विभाग 104 से 110 फीसदी के बीच बारिश को सामान्य से बेहतर मानता है। यह फसलों के लिए अच्छा संकेत है। IMD के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि 2025 में 105% यानी 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। 4 महीने के मानसून सीजन के लिए लॉन्ग पीरियड एवरेज (LPA) 868.6 मिलीमीटर यानी 86.86 सेंटीमीटर होता है। यानी मानसून सीजन में कुल इतनी बारिश होनी चाहिए। सामान्य से अधिक बारिश का अनुमानः मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल मराठवाड़ा और उससे सटे तेलंगाना में।

सामान्य से कम बारिश का अनुमानः बिहार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में।

मानसून 1 जून के आसपास केरल के रास्ते आता है। 4 महीने की बरसात के बाद यानी सितंबर के अंत में राजस्थान के रास्ते मानसून की वापसी होती है। कई राज्यों में यह 15 से 25 जून के बीच पहुंचता है।

IMD चीफ बोले- हीटवेव्स के दिन मई-जून में बढ़ेंगे

IMD चीफ ने कहा कि इस साल अल नीनो की स्थितियां नहीं बनेंगी। देश के कई हिस्सों में अभी भीषण गर्मी पड़ रही है। अप्रैल और जून में हीटवेव्स दिनों की संख्या में इजाफा होगा। इससे पावर ग्रिड पर प्रेशर बढ़ेगा और पानी की कमी होगी।

देश का 52 फीसदी खेतिहर इलाका मानसून पर निर्भर करता है। मानसून में पानी के स्त्रोतों की कमी पूरी होती है। ऐसे में सामान्य मानसून बड़ी राहत की खबर है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अब मानसून में बारिश के दिनों की कमी हो रही है और भारी बारिश की बढ़ोतरी हो रही है। इससे लगातार सूखा और बाढ़ के हालात बन रहे हैं।

योगी बोले- वक्फ की जमीनों पर मकान बनवाएंगेःलातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिसे बांग्लादेश पसंद, वो वहां चला जाए

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा- वक्फ की जमीनें वापस ली जाएंगी। इन पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल, विश्वविद्यालय बनेंगे। निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार होगा। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हो रही हिंसा पर सीएम ने हरदोई में कहा- लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। दंगाई डंडे से ही मानेंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद है, वह बांग्लादेश चला जाए।

उन्होंने कहा- बंगाल जल रहा है, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री के साथ-साथ सपा और कांग्रेस भी चुप हैं। ममता बनर्जी दंगाइयों को शांतिदूत कहती हैं और सेक्युलरिज्म के नाम पर उन्हें खुली छूट दे दी है। इस तरह की अराजकता पर लगाम लगनी चाहिए। वहां की कोर्ट को धन्यवाद दूंगा, जिसने वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है।

योगी मंगलवार को माधोगंज स्थित रुइया गढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा नरपत सिंह के विजय दिवस समारोह में भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 650 करोड़ रुपए की 729 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

1. वक्फ की जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बनाएंगे

वक्फ की जमीनें वापस ली जाएंगी। इन पर अस्पताल बनेंगे, गरीबों के लिए मकान बनेंगे, ऊंची इमारतें बनेंगी। यहां स्कूल, विश्वविद्यालय बनेंगे और निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार होगा, लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा कर गुंडागर्दी करने की छूट नहीं मिलेगी। लोग इसी वजह से परेशान हैं, क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट मची थी, अब वह रुकने वाली है।

2. सपा-कांग्रेस को परेशानी है कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे

इन लोगों को इसलिए परेशानी हो रही है, क्योंकि अब उनके गुर्गों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। वो गुर्गे जो पहले जनता को लूटते थे। जो भस्मासुर पाल रखे थे, अब उन्हें डर है कि कहीं वही इन्हें न डसने लगें। जो अकूत संपत्ति इकट्ठा की गई थी, उस पर डकैती न पड़ जाए।

इसलिए ये वक्फ के नाम पर जनता को गुमराह कर रहे हैं, आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन गुमराह होने की जरूरत नहीं है। हमें संविधान और बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर विश्वास रखना है और विकास की प्रक्रिया से जुड़ना है।

3. दंगाइयों का उपचार सिर्फ डंडा है

पहले रोजगार का अभाव था, अव्यवस्था थी। हमने योजनाओं को आगे बढ़ाया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पहले लोगों को पलायन करना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे-तीसरे दिन दंगे होते थे। इन दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है, बिना डंडे के वे मानेंगे नहीं।

4. ये लोग भारत की धरती पर बोझ बने हुए हैं

मुर्शिदाबाद को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी सब मौन हैं। वे धमकी पर धमकी दे रहे हैं और बांग्लादेश में जो हुआ, उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है, तो वहीं चले जाएं। ऐसे लोग भारत की धरती पर बोझ बन चुके हैं।

5. हरदोई के हुनर को पहचान मिलेगी

हरदोई में मेडिकल कॉलेज पूरी तरह तैयार हो चुका है और जल्द ही नर्सिंग कॉलेज भी शुरू होगा। गंगा एक्सप्रेसवे की 99 किलोमीटर की दूरी हरदोई से होकर गुजरेगी, जिससे दिल्ली और प्रयागराज की दूरी घटेगी। हरदोई की सीमा पर पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और यहां के हुनर को पहचान मिलेगी।

अब लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दूसरे राज्यों से लोग हरदोई आएंगे। डबल इंजन की सरकार विरासत का सम्मान करती है और विकास को गति देती है। प्रयागराज महाकुंभ इसका उदाहरण है, जहां 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। यह "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की भावना को दर्शाता है। भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और अगले दो वर्षों में हम तीसरे स्थान पर होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को फिर दी हिदायतःकहा- सतर्क रहकर देना चाहिए फैसला; हाईकोर्ट ने कहा था- लड़की खुद रेप की जिम्मेदार

सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन में दूसरी बार इलाहाबाद हाईकोर्ट को हिदायत दी कि उसे किसी भी केस में विवादित टिप्पणी करने से बचना चाहिए। हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को रेप के आरोपी को जमानत देते वक्त कहा था, 'पीड़ित लड़की ने खुद मुसीबत बुलाई, रेप के लिए वही जिम्मेदार है।'

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की 19 मार्च को की गई एक और टिप्पणी ''स्तन दबाना और पायजामे की डोरी तोड़ना रेप की कोशिश नहीं मानी जा सकती' पर सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की 10 अप्रैल की टिप्पणी का जिक्र किया।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट जज को जमानत के बारे में फैसला केस से जुड़े फैक्ट्स के आधार पर करना चाहिए। पीड़ित लड़की के खिलाफ गैरजरूरी टिप्पणी से बचना चाहिए। **जस्टिस गवई ने कहा-** केस में जमानत दी जा सकती है, लेकिन यह क्या बात हुई कि पीड़ित ने खुद ही मुसीबत बुलाई। जज को ऐसी टिप्पणी करते वक्त सतर्क रहना चाहिए।

इस पर SG तुषार मेहता ने कहा कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखाई भी देना चाहिए। इस तरह के आदेश को आम आदमी किस नजरिए से देखेगा, यह भी सोचना चाहिए।

खाने-पीने की चीजों के दाम में कमीःमार्च में महंगाई 6 साल के निचले स्तर पर, 3.34% रही रिटेल इन्फ्लेशन

24 न्यूज अपडेट

रिटेल महंगाई घटकर 5 साल 7 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। मार्च में ये 3.34% रही। इससे पहले अगस्त 2019 में महंगाई 3.28% पर थी।

मार्च से एक महीने पहले यानी, फरवरी में महंगाई 3.61% पर थी। सांख्यिकी मंत्रालय ने आज यानी, मंगलवार 15 अप्रैल को महंगाई के आंकड़े जारी किए।

महंगाई के बास्केट में लगभग 50% योगदान खाने-पीने की चीजों का होता है। इसकी महंगाई महीने-दर-महीने आधार पर 3.75% से घटकर 2.67% हो गई है। वहीं ग्रामीण महंगाई 3.79% से घटकर 3.25% और शहरी महंगाई 3.32% से बढ़कर 3.43% हो गई है।

फरवरी में रिटेल महंगाईः

फरवरी में महंगाई 7 महीने के निचले स्तर 3.61% पर आ गई थी।

खाने-पीने की महंगाई महीने-दर-महीने आधार पर 5.97% से घटकर 3.75% हो गई थी।

ग्रामीण महंगाई 4.59% से घटकर 3.79% और शहरी 3.87% से घटकर 3.32% हो गई थी।

मार्च में व्यापार घाटा बढ़कर 1.84 लाख करोड़ हुआःये पिछले महीने से 34% ज्यादा; देश में इंपोर्ट 11.4% बढ़ा

24 न्यूज अपडेट

इंपोर्ट में बढ़ोतरी के कारण भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा मार्च 2025 में बढ़कर 21.54 बिलियन डॉलर (1.84 लाख करोड़ रुपए) हो गया है। ये पिछले महीने की तुलना में 34% ज्यादा है।

फरवरी में व्यापार घाटा 14.05 बिलियन डॉलर (1.21 लाख करोड़ रुपए) था। वहीं मार्च में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 0.7% बढ़कर 41.97 बिलियन डॉलर (3.60 लाख करोड़ रुपए) पहुंच गया है।

देश में इंपोर्ट 11.4% बढ़ा

इंपोर्ट की बात करें तो मार्च में भारत का इंपोर्ट 63.51 बिलियन डॉलर 5.44 लाख करोड़ रुपए रहा। ये फरवरी के मुकाबले 1.02 लाख करोड़ ज्यादा है। पिछले महीने भारत में 4.42 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट हुआ था।

फरवरी में व्यापार घाटा 3 साल में सबसे कम रहा

व्यापार घाटा फरवरी 2025 में घटकर 14.05 बिलियन डॉलर (1.21 लाख करोड़ रुपए) हो गया था। ये घाटा अगस्त 2021 बाद से सबसे कम है था। फरवरी में मर्चेंडाइस एक्सपोर्ट 3.20 लाख करोड़ रुपए रहा। जनवरी में ये 3.16 लाख करोड़ रुपए था। इसमें 1.25% की बढ़ोतरी हुई थी।

फरवरी में इंपोर्ट की बात करें तो ये जनवरी के मुकाबले 13.59% कम रहा था। फरवरी में भारत का इंपोर्ट 4.42 लाख करोड़ रुपए रहा। ये जनवरी के मुकाबले 73,000 करोड़ रुपए कम था। जनवरी में भारत में 5.15 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट हुआ था।

सेंसेक्स 1578 अंक ऊपर 76,735 पर बंदःनिफ्टी 500 अंक चढ़कर 23,329 पर पहुंचा, NSE का रियल्टी इंडेक्स 6% चढ़ा

24 न्यूज अपडेट

शेयर बाजार में आज यानी मंगलवार, 15 अप्रैल को बड़ी तेजी रही। सेंसेक्स 1578 अंक (2.10%) चढ़कर 76,735 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 500 अंक (2.19%) की तेजी रही, ये 23,329 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी रही। इंडसइंड बैंक में 6.70%, टाटा मोटर्स में 4.61%, लार्सन एंड टुब्रो में 4.50%, एक्सिस बैंक में 4.23% और अडाणी पोर्ट्स में 4.13% की तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 49 में तेजी रही। NSE के सेक्टोरल इंडाइसेज में सबसे ज्यादा तेजी रियल्टी में 5.64%, ऑटो में 3.39%, फाइनेंशियल सर्विसेज में 3.28%, मेटल में 3.20% और मीडिया में 2.97% की रही।

UDA का 2025-26 बजट : हर दिन शहर के विकास पर खर्च होगा 2.55 करोड़, 931.66 करोड़ की समग्र योजना, 352.48 करोड़ के नए विकास कार्य प्रस्तावित

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) ने दिनांक 15 अप्रैल 2025 को अपने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की घोषणा की। कुल बजट राशि 931.66 करोड़ रुपये रखी गई है, जिसमें समान राशि आय और व्यय मदों में रखी गई है। इस बजट में विकास कार्यों हेतु कुल 669.42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें 316.94 करोड़ रुपये पूर्व स्वीकृत प्रगतिरत कार्यों के लिए तथा 352.48 करोड़ रुपये नवीन कार्यों के लिए आरक्षित हैं। संपूर्ण बजट में सर्वाधिक राशि विकास कार्यों पर खर्च की जा रही है — 669.42 करोड़ यानी कुल बजट का 71.85%, जिसमें भी अकेले नवीन विकास कार्यों पर 37.83% (352.48 करोड़) और प्रगतिरत कार्यों पर 34.02% (316.94 करोड़) व्यय होगा। यह स्पष्ट करता है कि प्राधिकरण का फोकस भूतपूर्व कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ नवाचार पर भी है। UDA का 2025-26 बजट एक दृष्टि से अत्यंत संतुलित और समर्पित प्रयास है जो शहरी अधोसंरचना, पर्यटन, ऊर्जा, खेल, स्वच्छता और ग्रामीण विकास जैसे बहुविषयी क्षेत्रों को समाहित करता है। पर्यटन स्थलों और झीलों पर निवेश से आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। खेलगांव, ऑक्सीजन हब, और स्वागत द्वार जैसे प्रोजेक्ट शहर की ब्रांडिंग में योगदान देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का व्यय अनुपात केवल ₹2% है, जबकि इनमें जनसंख्या एवं आधारभूत सुविधाओं की बड़ी मांग है। ऊर्जा एवं पर्यावरण क्षेत्र में अल्प निवेश के स्थान पर दीर्घकालिक हरित योजनाएं बढ़ाई जा सकती हैं।

नवीन विकास कार्यों पर 352.48 करोड़ रुपये का विशेष फोकस

UDA द्वारा 2025-26 में जिन प्रमुख नए विकास कार्यों की योजना बनाई गई है, उनका उद्देश्य शहर की आधारभूत संरचना को मजबूती देना, नागरिक जीवन को सुगम बनाना तथा पर्यटन, परिवहन और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। 352.48 करोड़ रुपये के इन प्रस्तावों में विविधता और बहुआयामी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

प्रमुख फ्लाईओवर और अंडरपास परियोजनाएँ:

बलीचा तिराहा (अहमदाबाद रोड) पर ग्रेड सेपरेटर निर्माण – 10 करोड़। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत यह योजना तत्काल क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत है।

प्रतापनगर से बलीचा के बीच SH-32 के नीचे दो लेन अंडरब्रिज का 4 लेन में विस्तार – 6 करोड़। यह कार्य यातायात का दबाव कम करेगा। आयड़ ब्रिज का विस्तार एवं नवीनीकरण – 7.50 करोड़। मौजूदा पुल की क्षमता बढ़ाकर यातायात सुगमता लाई जाएगी। रेलवे RUB निर्माण (नोखा, उमरड़ा क्षेत्र) – 6 करोड़। रेलवे विभाग के सहयोग से यह अति आवश्यक कनेक्टिविटी सुविधा होगी।

सीवरेज और जल निकासी परियोजनाएँ:

नवरत्न कॉम्पलेक्स क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क निर्माण – 7 करोड़। इससे दक्षिणी विस्तार क्षेत्र में जल निकासी समस्या हल होगी।

एकलिंगपुरा से आयड़ नदी तक नया नाला निर्माण –3 करोड़

परशुराम चौराहा से जनकपुरी तक सतेरिया नाला निर्माण – 2.5 करोड़ मानसरोवर कॉलोनी तक समतानगर BG नगर से नए ड्रेनेज निर्माण – 3 करोड़।

शहर सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास:

रामगिरी पहाड़ी को ऑक्सीजन हब एवं पर्यटन स्थल रूप में विकास – 2 करोड़। यह स्थल ट्रैकिंग, व्यू पॉइंट्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए विकसित किया जाएगा। फतहसागर झील परिधीय क्षेत्र (रानी रोड) का सौंदर्यीकरण व यूटिलिटी शिफ्टिंग – 3 करोड़। इसमें पाथवे, सुदृढ़ सड़क और लाइन शिफ्टिंग शामिल है। देबारी, अंबेरी, बलीचा पर स्वागत द्वार निर्माण – 4 करोड़। शहर की छवि को पर्यटन हेतु सुसज्ज बनाने की दिशा में यह प्रयास होगा। स्थानीय जनजातीय चित्रकारों से शहर में चित्रकारी कार्य – 1 करोड़। यह स्थानीय कला को बढ़ावा देगा और शहर की दीवारें जीवंत बनेंगी।

आवासीय योजनाओं का विस्तार:

कलड़वास एवं नोहरा में नई आवासीय योजना के लिए बुनियादी सुविधाएं – 10 करोड़। इसमें सड़क, ड्रेनेज, जलापूर्ति, विद्युत व्यवस्था शामिल हैं। UDA कॉलोनियों में पार्कों का विकास – 4 करोड़। विभिन्न कॉलोनियों में हरित क्षेत्रों का सृजन एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 52 हेक्टेयर भूमि पर स्थित महाराणा प्रताप खेलगांव का विस्तार – 10.06 करोड़। इसमें स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज, क्रिकेट पैवेलियन व अन्य खेल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन सभी कार्यों को बजट 2025-26 में तत्काल क्रियान्वयन की दिशा में लाया जाएगा, जिससे शहर के विकास को नई गति मिलेगी।

UDA द्वारा 2025-26 में जिन प्रमुख नए विकास कार्यों की योजना बनाई गई है, उनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

24 न्यूज अपडेट

प्रमुख फ्लाईओवर और अंडरपास परियोजनाएँ:

बलीचा तिराहा (अहमदाबाद रोड) पर ग्रेड सेपरेटर **निर्माण - 10 करोड़**

प्रतापनगर से बलीचा के बीच SH-32 के नीचे दो लेन अंडरब्रिज का 4 लेन में विस्तार – 6 करोड़

आयड़ ब्रिज का विस्तार एवं नवीनीकरण – 7.50 करोड़

रेलवे RUB निर्माण (नोखा, उमरड़ा क्षेत्र) – 6 करोड़

सीवरेज और जल निकासी परियोजनाएँ:

नवरत्न कॉम्पलेक्स क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क निर्माण – 7 करोड़

एकलिंगपुरा से आयड़ नदी तक नया नाला निर्माण – 3 करोड़

परशुराम चौराहा से जनकपुरी तक सतेरिया नाला निर्माण – 2.5 करोड़

मानसरोवर कॉलोनी तक समतानगर BG नगर से नए ड्रेनेज निर्माण – 3 करोड़

शहर सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास:

रामगिरी पहाड़ी को ऑक्सीजन हब एवं पर्यटन स्थल रूप में विकास – 2 करोड़

फतहसागर झील परिधीय क्षेत्र (रानी रोड) का सौंदर्यीकरण व यूटिलिटी शिफ्टिंग – 3 करोड़

देबारी, अंबेरी, बलीचा पर स्वागत द्वार निर्माण – 4 करोड़

स्थानीय जनजातीय चित्रकारों से शहर में चित्रकारी कार्य – 1 करोड़

आवासीय योजनाओं का विस्तार:

कलड़वास एवं नोहरा में नई आवासीय योजना के लिए बुनियादी सुविधाएं – 10 करोड़

UDA कॉलोनियों में पार्कों का विकास – 4 करोड़

52 हेक्टेयर भूमि पर स्थित महाराणा प्रताप खेलगांव का विस्तार – 10.06 करोड़

63.21 करोड़ रुपये की लागत से 20 बड़ी सड़कों का निर्माण एवं सुधार

UDA ने कुल 99.45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले 20 प्रमुख सड़क कार्यों को मंजूरी दी है, जिनमें से 63.21 करोड़ रुपये इस वित्तीय वर्ष में व्यय किए जाएंगे। इन सड़कों का चयन ट्रैफिक दबाव, मास्टर प्लान, कॉलोनी विकास तथा सामाजिक महत्त्व को ध्यान में रखकर किया गया है।

प्रमुख सड़क कार्य इस प्रकार हैं:

दक्षिण विस्तार योजना (B और C ब्लॉक) – आंतरिक सड़कों का निर्माण – 3.10 करोड़

मादड़ी अंडरपास से काला भाटा तक सड़क चौड़ीकरण – 2 करोड़

मेगा आवास योजना से NH-27 तक 100 फीट मास्टर प्लान रोड – 5 करोड़

माली कॉलोनी - J.C. बॉस रोड पर RCA योजना से राडाजी तक 60 फीट सड़क – 95 लाख

एफसीआई गोदाम से हिरणमगरी सेक्टर-3 से होकर प्रतापनगर-बलीचा जंक्शन तक दोनों ओर इंटरलॉकिंग टाइल्स – 1.60 करोड़

मीरा नगर स्कीम (शोभागपुरा सर्कल से GSS तक) 100 फीट सड़क सुदृढ़ीकरण – 6 करोड़

आरके सर्कल से शोभागपुरा सर्कल तक व्हाइट टॉपिंग तकनीक से सड़क सुधार – 5 करोड़

फतहपुरा चौराहा से साइफन चौराहा तक सड़क एवं नाला निर्माण – 7 करोड़

सीता माता मंदिर से जल बुर्ज, सीसारमा तक सड़क सुधार – 1.75 करोड़

खीमच माता मंदिर से देवाली तिराहा होते हुए मइया चौराहा तक रोड सुदृढ़ीकरण – 4 करोड़

बड़ी जंक्शन (टाइगर हिल) से प्रताप गौरव केंद्र, बड़गांव तक सड़क सुधार – 1.5 करोड़

राजीव गांधी पार्क से हवाला कला गांव तक सड़क निर्माण – 1 करोड़

नारायण सेवा संस्थान से हाथीधरा गांव तक 60 फीट मुख्य सड़क का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण – 1 करोड़

मीरा नगर योजना क्षेत्र को जोड़ने वाली 80 फीट मास्टर प्लान सड़क – 4.5 करोड़

पुराना RTO से ढीकली तक 60 फीट सड़क का व्हाइट टॉपिंग सुधार – 3 करोड़

शोभागपुरा सर्कल से GSS (मीरा नगर योजना) तक 100 फीट सड़क सुधार – 6 करोड़

अंबेरी नीलकंठ महादेव से पुरोहितों का तालाब तक 80 फीट मास्टर प्लान सड़क – 3.5 करोड़

जैव-विविधता पार्क से NH-8, अंबेरी तक 100 फीट सड़क फॉर्मेशन कार्य – 2.5 करोड़

NH-8 से जैव-विविधता पार्क तक 60 फीट मास्टर प्लान सड़क का निर्माण – 2.61 करोड़

पुरोहितों का तालाब से अंबेरी तक 100 फीट चौड़ी सड़क पर डामरीकरण – 6.2 करोड़

इन कार्यों से उदयपुर की मास्टर प्लान कनेक्टिविटी को बल मिलेगा, यातायात सुगमता बढ़ेगी और कॉलोनियों में आवागमन की स्थितियाँ सुदृढ़ होंगी।

UDA ने कुल 99.45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले 20 प्रमुख सड़क कार्यों को मंजूरी दी है, जिनमें से 63.21 करोड़ रुपये इस वित्तीय वर्ष में खर्च किए जाएंगे।

प्रमुख कार्य:

दक्षिण विस्तार योजना B और C ब्लॉक की सड़कें – 3.10 करोड़

मादड़ी अंडरपास से काला भाटा तक सड़क चौड़ीकरण – 2 करोड़

मेगा आवास योजना से NH-27 तक 100 फीट मास्टर प्लान रोड – 5 करोड़

माली कॉलोनी-JC बॉस रोड पर RCA योजना से राडाजी तक 60 फीट सड़क – 95 लाख

एफसीआई गोदाम से हिरणमगरी सेक्टर-3 से प्रतापनगर-बलीचा जंक्शन तक इंटरलॉकिंग टाइल्स – 1.6 करोड़

शोभागपुरा सर्कल से GSS (मीरा नगर स्कीम) तक 100 फीट सड़क सुधार – 6 करोड़

आरके सर्कल से शोभागपुरा तक व्हाइट टॉपिंग सुधार – 5 करोड़

फतहपुरा से साइफन चौराहा तक सड़क एवं नाला कार्य – 7 करोड़

खीमच माता मंदिर से मइया चौराहा तक रोड सुधार – 4 करोड़

बड़ी जंक्शन से प्रताप गौरव केंद्र, बड़गांव तक रोड सुधार – 1.5 करोड़

ड्रेनेज परियोजनाओं हेतु कुल 23.70 करोड़ रुपये स्वीकृत

UDA ने वर्ष 2025–26 में वर्षा ऋतु के दौरान जलभराव से निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ड्रेनेज नेटवर्क के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण की विशेष योजना बनाई है। इसके अंतर्गत कुल 23.70 करोड़ **रुपये का बजट विभिन्न क्षेत्रों में निम्नानुसार व्यय किया जाएगा:**

गोरधन विलास, बलीचा, सवीना, सवीना खेड़ा, तितरड़ी – कॉलोनियों में नए ड्रेनेज नेटवर्क निर्माण हेतु – 2.50 करोड़

परशुराम चौराहा से जनकपुरी तक सतेरिया नाले का निर्माण – 2.50 करोड़

एकलिंगपुरा से आयड़ नदी तक नया नाला निर्माण – 3 करोड़

मनवाखेड़ा, एकलिंगपुरा, बेड़वास, वाडा–ढीकली आदि कॉलोनियों में ड्रेनेज कार्य – 2.50 करोड़

भुवाणा सर्कल से मेवाड़ हॉस्पिटल जंक्शन तक 100 फीट नाला निर्माण – 2.20 करोड़

समतानगर, बीजी नगर, मानसरोवर कॉलोनी तक नया ड्रेनेज कार्य – 3 करोड़

चित्रकूट नगर, मीरा नगर योजना क्षेत्र में ड्रेनेज कार्य – 2 करोड़

शोभागपुरा, भुवाणा, रघुनाथपुरा, बेदला, सापेटिया क्षेत्रों में कॉलोनियों हेतु ड्रेनेज – 3.50 करोड़

बड़गांव, बड़ी, लियांस का गुड़ा, थूर, सीसारमा क्षेत्र की कॉलोनियों में ड्रेनेज – 2.50 करोड़

इन कार्यों का उद्देश्य UDA क्षेत्र की मुख्य कॉलोनियों को मानसून के दौरान जल प्लावन की स्थिति से बचाना एवं आपदा राहत सुनिश्चित करना है।

UDA क्षेत्र में जलनिकासी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 9 विभिन्न क्षेत्रों में ड्रेनेज कार्यों हेतु कुल 23.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। प्रमुख क्षेत्रों में – गोरधन विलास, सवीना, तितरड़ी, मनवाखेड़ा, चित्रकूट नगर, भुवाणा, सापेटिया, सीसारमा, बड़गांव, ढीकली आदि शामिल हैं।

खेल, पर्यटन और ऊर्जा में समन्वित विकास

UDA ने 2025-26 में खेल, पर्यटन और ऊर्जा के क्षेत्र में बहुआयामी विकास की योजना बनाई है:

खेलगांव का उन्नयन एवं नई सुविधाएँ:

चित्रकूट नगर योजना के पास स्थित 52 हेक्टेयर भूमि पर बने महाराणा प्रताप खेलगांव में अनेक अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

खेलगांव में ऑल वेदर स्विमिंग पूल के निर्माण पर 6.50 करोड़ खर्च होंगे।

क्रिकेट स्टेडियम के पैवेलियन निर्माण हेतु 1.56 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नवीन व विविध खेलों की सुविधाएं, जैसे ओपन जिम, बैडमिंटन हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट आदि हेतु 1 करोड़।

शूटिंग रेंज निर्माण हेतु 50 लाख तथा इंडोर जिम के उपकरण स्थापित करने हेतु 50 लाख का बजट स्वीकृत है।

पर्यटन एवं झील विकास:

पर्यटन दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण फतहसागर झील की नियमित सफाई हेतु 3 करोड़ स्वीकृत।

यह कार्य निविदा प्रक्रिया से चयनित संवेदक द्वारा किया जाएगा और वर्ष भर श्रमिकों की तैनाती रहेगी।

रामगिरी पहाड़ी को ऑक्सीजन हब एवं पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें हरित क्षेत्र, पाथवे, दर्शक बिंदु आदि शामिल होंगे। इसके लिए 2 करोड़ का बजट है।

देबारी, अंबेरी, बलीचा जैसे प्रवेश बिंदुओं पर सुसज्जित स्वागत द्वारों का निर्माण किया जाएगा – 4 करोड़।

स्थानीय/जनजातीय चित्रकारों द्वारा शहर के प्रमुख स्थानों पर चित्रकारी कार्य – 1 करोड़। इससे सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिलेगा।

ऊर्जा एवं विद्युतिकरण:

UDA क्षेत्र की प्रमुख सड़कों, कॉलोनियों और पार्कों में सोलर स्ट्रीट लाइट्स और हाइ मास्ट पोल्स की स्थापना की जाएगी। कुल 8.95 करोड़ के बजट में निम्नलिखित कार्य होंगे:

रामगिरी पहाड़ी एवं रत्नागिरी वन क्षेत्र में सोलर हाईमास्ट – 2 करोड़

NH-76 मार्ग पर रामगिरी–बलीचा रोड पर ऑक्टागोनल पोल – 1.85 करोड़

जोइगी तालाब व नेला तालाब क्षेत्र में सोलर लाइट्स – 1.5 करोड़

दक्षिण विस्तार योजना रोड (SH-32 से NH-8) पर पोल – 1.30 करोड़

सीसारमा–नांदेश्वर रोड पर सोलर पोल – 1.30 करोड़

लखावली तालाब क्षेत्र में सजावटी पोल – 1 करोड़

यह समेकित विकास योजना न केवल खेल सुविधाओं और पर्यटन में इजाफा करेगी, बल्कि हरित ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को भी सशक्त बनाएगी।

फतहसागर झील की सफाई हेतु – 3 करोड़

स्विमिंग पूल, क्रिकेट स्टेडियम, शूटिंग रेंज आदि सहित खेलगांव विकास – 10.06 करोड़

सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइट्स व हाइ मास्ट व्यवस्था – 8.95 करोड़

चित्रकूट नगर, मीरा नगर, लखावली, नेला तालाब आदि में पोल और लाइट्स लगाई जाएंगी।

ग्रामीण क्षेत्र और स्वच्छता पर विशेष ध्यान

UDA के अधिकार क्षेत्र में वर्तमान में 47 ग्राम पंचायतें एवं 136 गाँव सम्मिलित हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों द्वारा निरंतर आंतरिक विकास कार्यों की मांग की जाती रही है, जिन्हें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राधिकरण तक पहुँचाया गया है।

इन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा 20 करोड़ का बजट इन परिधीय ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वीकृत किया गया है:

मुख्य सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत

श्मशान भूमि का विकास (शेड, पानी की व्यवस्था, पेवर ब्लॉक, हरित क्षेत्र)

सामुदायिक भवनों का निर्माण

खेल मैदान एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य स्थानों का निर्माण

ये कार्य ग्राम स्तर पर आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने में सहायक होंगे।

स्वच्छता कार्यों पर विशेष बल:

UDA क्षेत्र के नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने हेतु 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं लागू की जाएंगी:

घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली: प्रत्येक कॉलोनी व मोहल्ले से प्रतिदिन कचरा संग्रह हेतु वाहन सेवा चलाई जाएगी।

संपूर्ण सड़क एवं फुटपाथ सफाई: नगर निगम की तर्ज पर नियमित सफाई तंत्र लागू होगा जिसमें कर्मचारी, सुपरवाइजर, वाहन और मशीनरी की व्यवस्था रहेगी।

मानसून पूर्व नालों की सफाई अभियान: जलभराव से बचने के लिए सभी खुले व बंद नालों की ग्रीष्मकाल में व्यापक सफाई की जाएगी।

सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ेदान एवं सूचना पैनल्स की स्थापना की जाएगी।

प्रत्येक ज़ोन में नियंत्रण कक्ष/निरीक्षण प्रणाली स्थापित की जाएगी जिससे शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हो।

शहरी स्वच्छता मूल्यांकन (Swachh Survekshan) की तैयारी के तहत सभी संबंधित मानकों पर काम किया जाएगा।

यह समूची व्यवस्था नगर निगम उदयपुर द्वारा निष्पादित की जाएगी। व्यय का वहन उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और आवश्यक राशि नगर निगम को हस्तांतरित की जाएगी। यह पहल न केवल स्वच्छता में सुधार लाएगी, बल्कि उदयपुर को एक आदर्श स्वच्छ पर्यटक नगरी के रूप में स्थापित करेगी।

UDA क्षेत्र के नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने हेतु 11 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके तहत:

घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था लागू की जाएगी।

मुख्य सड़कों और आंतरिक मार्गों की नियमित सफाई करवाई जाएगी।

मानसून पूर्व सभी नालों की सफाई एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा।

यह समस्त कार्य नगर निगम उदयपुर द्वारा निष्पादित किए जाएंगे, जबकि वित्तीय व्यय का वहन UDA द्वारा किया जाएगा। यह व्यवस्था शहर की स्वच्छता को बेहतर बनाएगी और उदयपुर को स्वच्छ भारत मिशन के मापदंडों पर अग्रणी शहरों में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी।

UDA परिधीय ग्रामों में सड़क, सामुदायिक भवन, श्मशान आदि विकास हेतु – 20 करोड़

घर-घर कचरा संग्रहण, सफाई एवं नालों की सफाई हेतु – 11 करोड़ (नगर निगम द्वारा क्रियान्वयन)

राजस्थान के पूर्व मंत्री खाचरियावास के घर ED की रेड:19 ठिकानों पर पहुंची टीम, रियल एस्टेट निवेश में 48 हजार करोड़ के घोटाले का मामला

24 न्यूज़ अपडेट

प्रवर्तन निदेशालय (ED) आज जयपुर सहित देश के 19 अलग-अलग ठिकानों पर छापा मार रहा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास का आवास भी इसमें शामिल है। सुबह करीब 5 बजे टीमें खाचरियावास के आवास पर पहुंच गई थीं। यह मामला रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PACL) में हुए 48 हजार करोड़ के घोटाले से जुड़ा है।

ED से मिली जानकारी के अनुसार, प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोगों के नाम पर PACL में घोटाले का पैसा ट्रांसफर हुआ था। अधिकांश पैसा प्रॉपर्टी और अन्य सेक्टर में लगा दिया गया।

समर्थकों से पुलिस की बहस

पूर्व मंत्री के घर छापेमारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में जयपुर के सिविल लाइंस स्थित आवास पर समर्थक पहुंच गए। समर्थकों ने इस कार्रवाई का विरोध किया। मौके पर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने पूर्व मंत्री के आवास के बाहर खड़ी समर्थक की गाड़ी को लेकर आपत्ति जताई। उसी गाड़ी पर खड़े होकर समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान समर्थकों की पुलिसकर्मियों से बहस भी हो गई।

हालात को देखते हुए ईडी की टीम ने जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉज जोसफ और डीसीपी साउथ दिगंत आनंद से बात की। इसके बाद मौके पर तीन थानों की फोर्स भेजी गई। इस दौरान खाचरियावास भी आवास से बाहर आए और अपने समर्थकों को समझाया। तब जाकर मामला शांत हुआ।

लाखों लोगों के साथ हुई थी PACL में धोखाधड़ी

लाखों लोगों के साथ PACL में धोखाधड़ी हुई थी। इसके बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2016 को सेवानिवृत्त CJI आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कोर्ट ने कमेटी से कहा था कि पीएसीएल की संपत्तियों को नीलाम करके 6 महीने में लोगों को ब्याज सहित भुगतान करें।

SEBI के आकलन के अनुसार, PACL की 1.86 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो निवेशकों की जमा राशि की तुलना में 4 गुना है। PACL कंपनी की योजनाओं को अवैध मानते हुए SEBI ने 22 अगस्त 2014 को कंपनी के कारोबार बंद कर दिए थे। इसके चलते निवेशकों की पूंजी कंपनी के पास जमा रह गई। इसके बाद कंपनी व SEBI के बीच सुप्रीम कोर्ट में केस चला और SEBI जीत गई।

राजस्थान में 28 लाख लोगों ने 2850 करोड़ किए थे निवेश

17 वर्ष तक राज्य में रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली PACL में प्रदेश के 28 लाख लोगों ने करीब 2850 करोड़ और देश के 5.85 करोड़ लोगों ने कुल 49100 करोड़ का निवेश किया था। कंपनी पर बिहार, महाराष्ट्र, MP, असम, कर्नाटक, जयपुर ग्रामीण, उदयपुर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत आधे से ज्यादा राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं।

सबसे पहले जयपुर में इसका खुलासा होने पर FIR दर्ज हुई थी। जानकार सूत्रों की मानें तो इस केस में प्रताप सिंह की भागीदारी करीब 30 करोड़ की बताई जा रही है। ED की छापेमारी पूरी होने के बाद ही रिकवरी को लेकर कुछ कहा जा सकता है।

खाचरियावास ने कहा- जो इनके खिलाफ बोलता है, ED भेज देते हैं

प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा- ED केंद्र के अधीन है। इस डबल इंजन की सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता। मेरे परिवार के सदस्यों के यहां बेवजह सर्च चल रहा है। हम पूरा सर्च करवाएंगे। ED के अफसरों से हम पूरा सहयोग करेंगे। BJP सरकार को मेरे बोलने से इतना दर्द है कि छापे डलवा दिए। मैं पिछले डेढ़ साल से इनके खिलाफ बोल रहा हूं। जो BJP और इनकी सरकार के खिलाफ बोलता है, उसके घर ये ED भेज देते हैं। मैं बोल रहा था तो मुझे भी पहले से पता था कि ED तो एक दिन पहुंचेगी, यदि पहुंचेगी तो मैं भी तैयार हूं।

3000 में सालभर टोल टैक्स की छुट्टी, बिना रूके एक्सप्रेसवे पर भगा सकेंगे गाड़ी, क्या है नया टोल प्लान

24 न्यूज़ अपडेट

हाईवे, एक्सप्रेसवे पर सफर का मजा अब और बढ़ जाएगा. अब लॉग ड्राइव के दौरान आपको टोल प्लाजा पर बार-बार रुकना नहीं होगा. एक बार फर्राटे से कार ने रफ्तार भरी तो सीधे मंजिल पर जाकर रुकेंगे. सफर के दौरान टोल प्लाजा की बाधा अब खत्म होने वाली है. नई टोल पॉलिसी लागू होने वाली है. अगले 15 दिनों में नई टोल पॉलिसी टोल टैक्स सिस्टम लागू हो जाएंगे. नई टोल पॉलिसी के तहत अब एनुअल पास बनेंगे. यानी एक बार पास बनवाया तो सालभर टोल टैक्स भरने की छुट्टी. सरकार जल्द ही एक ऐसी टोल पॉलिसी लाने जा रही है, जो आपकी जेब पर बोझ कम करने वाली है, साथ ही साथ आपका टाइम भी बचेगा. एनुअल पास की मदद से आप बिना रोक-टोक हाईवे-एक्सप्रेसवे पर सफर कर सकेंगे. नए टोल सिस्टम के तहत अब किलोमीटर बेस्ड चार्जिंग सिस्टम लागू होगा. नए टोल सिस्टम के तहत देशभर में टोल प्लाजा हटेंगे . किलोमीटर बेस्ड चार्जिंग सिस्टम लागू होगा. यानी आप जितना किलोमीटर गाड़ी भगाओगे उतना ही टोल टैक्स भरना होगा. आपके लिए एनुअल टोल पास की भी सुविधा होगी. नई नीति में सरकार के तहत लोगों को अपने 3000 रुपये में एनुअल टोल पास मिलेगा. फास्टैग को एक बार 3000 रुपये के लिए रिचार्ज करवा लिया तो तो फिर सालभर टोल से छुट्टी मिल जाएगी. हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सरकार नई कार के साथ लाइफटाइम टोल प्लाजा पास पर भी विचार कर सकती है. 30 हजार में 15 सालों तक किसी भी टोल प्लाजा पर फ्री होकर आना-जाना कर सकते हैं. हालांकि लाइफटाइम पास को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है. यानी अगर सब प्लान के मुताबिक हुआ तो कुछ दिनों में आप बिना टोल प्लाजा पर रुके देशभर में घूम पाएंगे. एनुअल फास्टैग पास से पैसे और टाइम दोनों की बचत होगी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार, 14 अप्रैल 2025 को हुए एक इवेंट के दौरान कहा कि जल्द ही देश में नई टोल पॉलिसी लागू होगी. जल्द ही फिजिकल टोल बूथ हटा दिए जाएंगे. नए सिस्टम के लागू होने के बाद टोल टैक्स के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी. सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए टोल अपने आप ही कट हो जाएगा. सैटेलाइट के जरिए व्हीकल नंबर प्लेट की पहचान की जाएगी और ऑटोमेटिक ही टोल कट हो जाएगा. इस नए सिस्टम से मैनुअल टोल कलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी.

अफसरों की काली कमाई शेयर मार्केट-म्यूचुअल फंड में इंवेस्ट:सोने की चमक भी उन्हें खींच रही; अमेरिका-लंदन में मोटी फीस से पढ़ रहे घूसखोरों के बच्चे

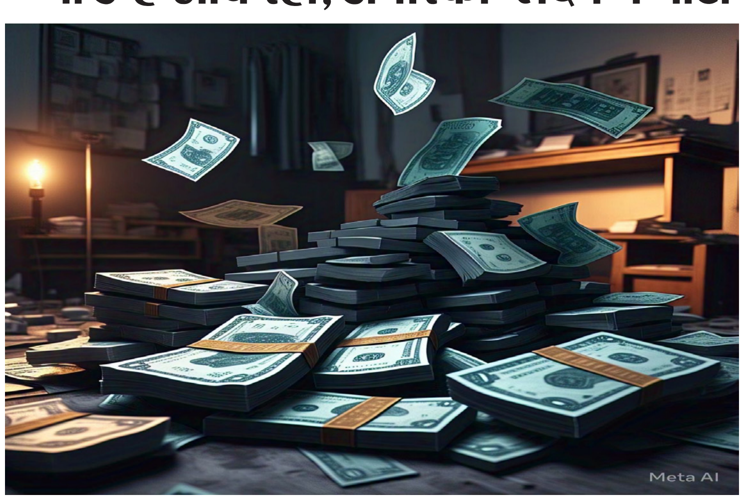

24 न्यूज़ अपडेट

प्रदेश में आय से अधिक संपत्तियों के मामलों में नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। घूस लेने वाले सरकारी अफसर-कर्मचारी अपनी काली कमाई को प्रॉपर्टी-गोल्ड की बजाय शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर दोगुना-तिगुना कर रहे हैं।

वहीं ज्यादातर अधिकारी बच्चों को विदेशों में महंगी एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं। एसीबी की रडार पर आए कई विभागों के अफसरों की पड़ताल में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है।

कई अफसरों के डीमैट खातों में अलग-अलग कंपनियों के शेयर, लाखों-करोड़ों के म्युचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मिला है। कई के पास एफडी और पॉलिसी में निवेश मिला है। हाल ही में सामने आए ऐसे कई मामलों का भास्कर टीम ने एनालिसिस किया।

केस- 1 : अफसर ने 1.34 करोड़ रुपए शेयर बाजार में लगाए

11 मार्च 2025 को एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के अधीक्षण अभियन्ता अविनाश शर्मा के 7 ठिकानों पर सर्च किया था।

सर्च में एसीबी ने 13 लाख रुपए नकद और आरोपी और उसके परिवारजनों के नाम 100 से अधिक प्रॉपर्टी के डॉक्युमेंट बरामद किए थे। एसीबी को 6 करोड़ 25 लाख रुपए काली कमाई का पता चला था।

चौंकाने वाली बात यह है कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में एक करोड़ 34 लाख रुपए के निवेश का हिसाब-किताब भी मिला। इसके अतिरिक्त आरोपी के बच्चों की शिक्षा संबंधित डॉक्युमेंट और अनेक पॉलिसियों में इंवेस्टमेंट के डॉक्युमेंट भी बरामद किए गए।

केस- 2 : म्यूचुअल फंड में 50 लाख रुपए का निवेश

16 फरवरी 2024 को जोधपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के अधिशाषी अभियन्ता दीपक मित्तल के कई ठिकानों पर छापेमारी हुई।

एसीबी ने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और हरियाणा के फरीदाबाद में 50 लाख रुपए कैश के अलावा आधा किलो गोल्ड और डेढ़ किलो चांदी के आभूषण मिले।

एसीबी को सर्च में संदिग्ध अधिकारी के पास 50 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड का निवेश भी मिला। इसके साथ ही अनेक बीमा पॉलिसियों में निवेश करना भी पाया गया।

बच्चों की शिक्षा सेंट जेवियर, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और एम्स गोरखपुर की फीस से संबंधित डॉक्युमेंट भी बरामद किए गए हैं।

केस- 3 : बीमा पॉलिसी में निवेश, विदेश में बच्चों की पढ़ाई

23 जनवरी को एसीबी ने जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) संजय शर्मा पर शिकंजा कसा। जयपुर, भरतपुर और यूपी के मुरादाबाद स्थित 10 ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई की।

एक मकान-भूखंड और प्लॉट के अलावा 25 बीघा जमीन के डॉक्युमेंट मिले। आरोपी अपने बच्चों की उच्च शिक्षा विदेश में कराने संबंधी डॉक्युमेंट, अनेक बीमा पॉलिसियों में निवेश के डॉक्युमेंट भी मिले हैं।

केस-4 : एफडी में निवेश किए 1.87 करोड़

18 दिसंबर को एसीबी ने जलदाय विभाग के डूंगरपुर के अधीक्षण अभियंता अनिल कछवाहा को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। सर्च में 9 लाख 22 हजार कैश मिले।

इसके अलावा 1 करोड़ 87 लाख से अधिक के एफडीआर व बचत पत्र, 1 करोड़ 16 लाख कीमत के दो भूखंड के डॉक्युमेंट, 88 लाख 32 हजार की रकम बैंक खातों में जमा सहित कुल 4 करोड़ 16 लाख से ज्यादा की चल-अचल संपत्ति के डॉक्युमेंट मिले।

विनोद कांबली की मदद के लिए आगे आया यह दिग्गज क्रिकेटर, हर महीने देगा 30 हजार

24 न्यूज़ अपडेट

स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली को इस मुश्किल समय में सुनील गावस्कर से मदद मिली है. कांबली को पिछले साल दिसंबर में मूत्र संक्रमण और ऐंठन की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज को लगभग दो सप्ताह तक ठाणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 1 जनवरी को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी. कांबली पिछले कुछ वर्षों से कई स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं. 2013 में उनकी दो हार्ट सर्जरी भी हुई है और उन्हें सचिन तेंदुलकर से कुछ वित्तीय सहायता भी मिली है.

कांबली पिछले साल दिसंबर में तब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने शिवाजी पार्क में दिग्गज कोच रमाकांत आचरेकर के स्मारक के उद्घाटन में भाग लिया था. इस कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे. भारत के लिए 17 टेस्ट और 104 वनडे खेलने वाले कांबली उस समय स्वस्थ नहीं लग रहे थे. उन्हें कुछ सप्ताह बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था. मुश्किल समय के दौरान, गावस्कर ने कहा था कि 1983 विश्व कप की टीम बाएं हाथ के बल्लेबाज का साथ देगी और अब उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है.

गावस्कर अपने CHAMPS फाउंडेशन के माध्यम से अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार हैं, जो जरूरतमंद पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की सहायता करता है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, चैंप्स फाउंडेशन, जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी, मुश्किल समय में कांबली के लिए वित्तीय सहायता लेकर आया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि कांबली को 1 अप्रैल से जीवन भर 30,000 रुपये की मासिक सहायता मिलेगी. साथ ही, चिकित्सा सहायता के रूप में भी 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. कांबली की मुलाकात गावस्कर से इस साल की शुरुआत में जनवरी में वानखेड़े स्टेडियम की 50वीं वर्षगांठ के समारोह के उद्घाटन समारोह के दौरान हुई थी. कांबली को चलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उन्होंने गावस्कर के पैर छूकर उनके प्रति सम्मान दिखाया था.

76वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस, राज्य स्तरीय समारोह, रक्तदान शिविर और पुलिस बैंड प्रदर्शन बुधवार को, मुख्यमंत्री आरपीए ग्राउंड में लेंगे परेड की सलामी

24 न्यूज़ अपडेट

जयपुर, 15 अप्रैल। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार, 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री श्री शर्मा सेरेमोनियल परेड की सलामी लेंगे तथा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक व पुलिस पदक प्रदान करेंगे। इस समारोह के बाद आरपीए में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। शाम को जवाहर सर्किल पर पुलिस बैंड का डिस्प्ले होगा। समस्त आयोजनों के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

महानिदेशक पुलिस श्री उत्कल रंजन साहू ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह आरपीए में बुधवार सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा आरपीए में पहुंच शहीद स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद परेड ग्राउंड पर मुख्य समारोह का आयोजन होगा। श्री शर्मा परेड का अभिवादन स्वीकार कर निरीक्षण करेंगे। तत्पश्चात सम्मानित होने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को पारितोषिक एवं मेडल प्रदान किया जाएगा।

श्री साहू ने बताया कि आरपीए के परेड ग्राऊंड में आयोजित होने वाली सेरेमोनियल परेड में राजस्थान पुलिस अकादमी, चतुर्थ एवं पांचवी बटालियन आरएसी, हाड़ी रानी बटालियन, एसडीआरएफ, जीआरपी, एमबीसी एवं ईआरटी की एक-एक प्लाटून के अलावा जयपुर पुलिस आयुक्तालय की तीन प्लाटून (निर्भया स्कवॉड प्लाटून, पुलिसकर्मी प्लाटून और यातायात प्लाटून) भाग लेंगी। सेरेमोनियल परेड में आरपीए के सेन्ट्रल बैंड की भागीदारी होगी।

आरपीए में ही होगा रक्तदान शिविर : डीजीपी श्री साहू ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह के मौके पर आरपीए की डिस्पेंसरी में आयोजित रक्तदान शिविर में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा रक्तदान किया जाएगा।

पुलिस बैंड की स्वर लहरियों का रहेगा आकर्षण : डीजीपी श्री साहू ने बताया कि इस समारोह के बाद शाम 7 बजे से जयपुर में जवाहर सर्किल स्थित पत्रिका गेट पर पुलिस बैंड की मनोहारी प्रस्तुति होगी। इसमें राजस्थान पुलिस कें सैन्ट्रल बैंड, हाड़ी रानी बटालियन और ब्रास बैंड द्वारा स्वर लहरियां बिखेरते हुए राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के गौरव का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर शहरवासियों को इस मनोहारी प्रस्तुति का लुत्फ उठाने का आह्वान किया है।

कर्नाटक का कांग्रेस नेता अजमेर से गिरफ्तार: वक्फ बिल पर दिया था भड़काऊ बयान, वीडियो से मचा था बवाल

24 न्यूज़ अपडेट

अजमेर | कर्नाटक के विवादास्पद वक्फ विधेयक 2025 को लेकर भड़काऊ वीडियो जारी करने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व पार्षद कबीर खान को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अजमेर पुलिस ने कर्नाटक पुलिस की सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे आदर्श नगर क्षेत्र से पकड़ा और कर्नाटक पुलिस के हवाले कर दिया। अजमेर एसपी वंदिता राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि कर्नाटक पुलिस को इनपुट मिला था कि कबीर खान अजमेर में छिपा हुआ है। इसके बाद अजमेर पुलिस की मदद से उसे दबोचा गया।

क्या है पूरा मामला

कबीर खान, जो कि कर्नाटक के दावणगेरे का निवासी और कांग्रेस का पूर्व पार्षद है, ने हाल ही में पारित वक्फ विधेयक 2025 के विरोध में एक बेहद भड़काऊ वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उसने युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया था, जिससे पूरे राज्य में तनाव का माहौल बन गया। वीडियो में कबीर खान ने कथित रूप से कहा— "बसों और ट्रेनों में आग लगा दो... कुछ लोगों को अपनी जान कुर्बान करने दो... हर शहर में आठ से दस मौतें होनी चाहिए।" वह आगे कहता है— "पोस्टर और याचिकाओं से कुछ नहीं होगा... सिर्फ तबाही ही असर करेगी।"

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसे लेकर जबरदस्त विरोध हुआ और पुलिस ने उसके खिलाफ आईटी एक्ट व देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया।

पुलिस कर रही आगे की कार्रवाई

गिरफ्तारी के बाद अब कर्नाटक पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर अपने राज्य ले गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूछताछ और जांच में तेजी लाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वीडियो के पीछे कोई संगठित साजिश तो नहीं थी और क्या कबीर खान का किसी कट्टरपंथी संगठन से संपर्क रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं, कई सामाजिक संगठनों ने ऐसे बयान की निंदा करते हुए इसे समाज में जहर घोलने वाला बताया है।

एसी कमरे में बैठक में बिजली समस्या पर गहन मंथन, मंत्रीजी हुए गुस्सा, एक्सईएन और जेईएन को एपीओ, कहा-निर्बाध बिजली आपूर्ति सरकार की प्राथमिकता

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, उदयपुर। अधिकारी हीट वेव पर एसी कमरों में चर्चा करते हैं तो मंत्रीजी भी एसी कमरों में बिजली की समस्या पर गहन मंथन के दौरान जनता की तकलीफों का अहसास करते हैं और विद्युत निगम के अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों की ओर से कॉल रिसीव नहीं करने की शिकायत पर एपीओ कर देते हैं। इस बीच उदयपुर शहर में ही कई इलाकों में बिजली गुल हो जाती है, फिर आती जाती है और लोग घरों में ही पसीना पसीना हो जाते हैं। कूल माहौल में चर्चा के ये सिलसिले ना जाने कब तक चलेंगे मगर लगता है कि इस बैठक मिले निर्देशों के बाद जनता को राहत जरूर मिलने की संभावना है। कितना अच्छा हो कि ऐसी बैठकें भरी दुपहरी में उसी तापक्रम पर हुआ करें जो जनता महसूस करती है और पसीना पसीना होकर परेशान हो जाया करती है। दूसरी तरफ निचले स्तर पर काम करने वाले अफसर दबी जुबान में जनता से कहते हैं कि बिजली की मांग व आपूर्ति में जो अंतर है, उसे देख कर वे कर भी क्या सकते हैं। कई बार वीवीआईपी जगहों और लोगों को देखना पड़ता है। ऐसे में बिजली कट का दंश आम लोगों को ही भुगतना होता है। बहरहाल, प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि गर्मी के मौसम में विद्युत की मांग तेजी से बढ़ती है। फीडर ओवरलोड होने से ट्रिपिंग की समस्या रहती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए संकल्पबद्ध है। अधिकारी पूर्ण गंभीरता और संवेदनषीलता के साथ काम करते हुए ऐसे इंतजाम करें कि गर्मी में डिमाण्ड बढ़ने पर सिस्टम ओवरलोड नहीं हो और जीरो ट्रबल रहे। नागर मंगलवार को जिला परिषद सभागार में ऊर्जा विभाग के उदयपुर, राजसमंद और सलूम्बर जिले के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में ऊर्जा राज्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों तथा प्रषासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में तीनों जिलों में विभागीय योजनाओं, मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवष्यक दिषा-निर्देष दिए। साथ ही गर्मी के मद्देनजर विभाग की ओर से तैयार समर प्लान, अब तक की कार्यवाही आदि पर विस्तृत चर्चा की। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलक्टर नमित मेहता, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, गोगुन्दा विधायक प्रताप गमेती, सलूम्बर विधायक शांतादेवी, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, राजसमंद जिला प्रमुख रतनीदेवी, समाजसेवी गजपालसिंह, मावली विधायक पुष्कर डांगी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता उदयपुर आईआर मीणा, अधीक्षण अभियंता उदयपुर के आर मीणा, अधीक्षण अभियंता राजसमंद बीएस शर्मा, अधीक्षण अभियंता सलूम्बर राकेष सोनी सहित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मंत्री ने कराया फोन, जेईएन ने नहीं उठाया, एपीओ

बैठक में नागर से शिकायत की गई कि उदयपुर के मावली क्षेत्र के खेमली में जेईएन चंद्रप्रकाश मेघवाल जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठता। वहीं हिरणमगरी में एक्सईएन का अता-पता ही नहीं है। इस बीच मंत्री नागर ने अपने पीए से कहा कि खेमली के जेईएन चंद्रप्रकाश मेघवाल को फोन लगाओ। मेघवाल ने यह कॉल नहीं उठाया तो नाराज हुए नगर ने मेघवाल को APO करने के आदेश दे दिए। इसके बाद अजमेर विद्युत वितरण निगम उदयपुर के एसई केएल मीणा ने खेमली के जेईएन चंद्रप्रकाश मेघवाल को एपीओ कर दिया। वहीं हिरणमगरी वाले एक्सईएन आईएम मंसूरी की शिकायत को लेकर स्थानीय अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वे मेडिकल पर हैं और वीआरएस अप्लाई कर रखा है। मंत्री ने कहा कि है वहां पर ऐसी स्थिति में दूसरा एक्सईएन लगाए ताकि जनता और जनप्रतिनिधियों की समस्या दूर हो सके।

औद्योगिक क्षेत्र में सुधारें बिजली व्यवस्था

बैठक में राज्यमंत्री की अनुमति से औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात रखी। इसमें औद्योगिक क्षेत्र जीएसएस पर पर्याप्त स्टाफ व संसाधन उपलब्ध कराने, ट्रांसफर्मर में जीओ-डीओ सिस्टम लगाने सहित अन्य समस्याएं रखीं। राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देषित करते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में ट्रिपिंग की समस्या से बहुत परेषानी होती है। उन्होंने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सर्वे कराकर जीओ-डीओ सिस्टम के लिए संभावनाएं तलाषने हुए सभी जरूरी उपाय सुनिष्चित करने के निर्देष दिए। साथ ही उन्होंने ठेके पर चल रहे जीएसएस की लगातार मोनिटरिंग करने के लिए भी पाबंद किया।

अवैध कनेक्शन हटाएं, फीडर लोस को सुधारें

बैठक में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने खांजीपीर क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन होने की बात कही। राज्यमंत्री ने संबंधित अधिषासी अभियंता व सहायक अभियंता से जवाब-तलब किया। अधिकारियों ने बताया कि अवैध कनेक्षन की समस्या है तथा फीडर लोस भी 35 प्रतिशत से अधिक है। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए फीडर इंचार्ज बदलने के निर्देष दिए। साथ ही उन्होंने जिला प्रषासन व पुलिस का सहयोग लेकर विषेष अभियान चलाते हुए सभी अवैध कनेक्षन हटवाने तथा फीडर लोस की स्थिति में दो माह में सुधार लाने के लिए पाबंद किया।

अधिकारी फील्ड में जाएं, आमजन को दें त्वरित राहत

ऊर्जा राज्यमंत्री ने विद्युत निगम के सभी अधिकारियों को नियमित रूप से फील्ड विजिट करने के निर्देष दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर देखें, ताकि वे समस्याओं के बारे में जानकर उनका समाधान कर सकें। उन्होंने आमजन की षिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान करने तथा लोगों को संतोषप्रद जवाब देने के लिए भी पाबंद किया।बैठक में विद्युत जनित हादसों को लेकर भी चर्चा की गई। मंत्री नागर ने फीडर शटडाउन को लेकर ओटीपी आधारित ऑनलाइन सिस्टम विकसित किए जाने की बात कही, ताकि हादसों में कमी लाई जा सके।

टेंट हाउस गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान; 7 दमकलों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट, चित्तौड़गढ़। शहर के सेंथि इलाके में सोमवार सुबह महावीर टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम लपटों और काले धुएं से घिर गया। आग की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। शॉर्ट सर्किट की आशंका, लाखों का नुकसान प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि जांच के बाद ही पुष्टि संभव होगी। गोदाम में टेंट, गद्दे, कुर्सियां, पंखे, जनरेटर और अन्य सजावटी सामान रखा हुआ था, जो आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गया। टेंट हाउस के मालिक राकेश भड़कत्या के अनुसार, नुकसान का आंकलन लाखों से करोड़ों तक पहुंच सकता है। गेट खोलते ही आग ने लिया विकराल रूप राकेश और उनके कर्मचारी जब सुबह गोदाम पहुंचे, तब आग कम दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही मुख्य गेट खोला गया, हवा लगते ही आग ने विकराल रूप ले लिया। तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की 7 गाड़ियों ने चार घंटे में पाया काबू चूंकि फायर ब्रिगेड कार्यालय पास ही स्थित था, दमकल की गाड़ियां कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच गईं। नगर परिषद की पांच, जिंक की एक और बिरला की एक दमकल सहित कुल 7 दमकलों ने चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अंदर घुसी भारी धुएं और जलते सामान के कारण दमकल कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दीवार तोड़कर दमकल को दिलाई अंदर तक पहुंच सदर थाना अधिकारी निरंजन प्रताप सिंह के नेतृत्व में जेसीबी मशीन बुलवाकर गोदाम की पीछे की दीवार तोड़ी गई, जिससे दमकल गाड़ियां अंदर तक जा सकीं और आग को नियंत्रित किया जा सका।

स्थानीय लोगों ने भी निभाई जिम्मेदारी-आग की खबर मिलते ही आस-पास के लोग मदद के लिए दौड़े। कई लोगों ने साहस दिखाते हुए जलते गोदाम में घुसकर जो सामान बचाया जा सकता था, उसे बाहर निकालने में मदद की। स्थानीय लोगों की तत्परता से कुछ सामग्री को बचा लिया गया।

सुरक्षा उपायों की कमी उजागर- घटनास्थल पर न तो कोई फायर अलार्म सिस्टम था और न ही आग बुझाने के उपकरण। इस लापरवाही के कारण आग पर समय रहते नियंत्रण नहीं हो पाया और नुकसान अधिक हुआ। यह घटना आग से सुरक्षा उपायों के प्रति लापरवाह रवैये को भी उजागर करती है।

जांच जारी- फिलहाल पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमें आग लगने के कारणों की जांच में जुटी हैं। विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद ही नुकसान का वास्तविक आंकलन और आग लगने का स्पष्ट कारण सामने आ सकेगा।

भीलवाड़ा में पुलिस दिवस के आयोजन शुरू:गर्ल्स स्कूल में क्विज कंपीटिशन, राजस्थान पुलिस से जुड़े सवाल पूछे; SP देंगे प्राइज

24 न्यूज अपडेट

राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्कूली छात्रों में जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मंगलवार को जिला स्तरीय क्विज कॉन्टेस्ट किया गया। इसके अलावा स्कूल के बच्चों को भीलवाड़ा के विभिन्न थानों और सिटी कंट्रोल रूम में स्थित अभय कमांड सेंटर का विजिट करवाया जाएगा। एएसपी और परीक्षा की नोडल अधिकारी अदिति चौधरी ने बताया- राजस्थान पुलिस दिवस-2025 के उपलक्ष्य में स्कूली छात्र/छात्राओं की जिला स्तरीय क्विज कंपीटिशन का आयोजन आज गर्ल्स स्कूल में किया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहयोग से आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में क्लास 9 से 12 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने भाग लिया।

100 नंबर की है प्रतियोगिता

यह प्रतियोगिता 100 मार्क्स की है। इसमें राजस्थान पुलिस के बारे में सामान्य जानकारी, राजस्थान पुलिस संगठन की संरचना,कार्यप्रणाली, नवीन आपराधिक कानून, राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित "राजकॉप" नागरिक ऐप की जानकारी, यातायात नियमों की जागरूकता, साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा से संबधित जानकारी, महिला सुरक्षा से संबधित सामान्य जानकारी संबंधी प्रश्न पूछे गए। प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज 1500 रुपए कैश और सर्टिफिकेट, सेकेंड को 1000 रुपए कैश और सर्टिफिकेट एवं थर्ड रहने वाले को 500 रुपए कैश और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसके साथ ही पांच प्रतियोगियों को कंसोलेशन प्राइज 100 रुपए कैश और सर्टिफिकेट एसपी धर्मेंद्र सिंह देंगे। यहां से विजेता स्टूडेंट संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके अलावा आज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। कल 16 अप्रैल को परेड और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा।

नितिन गडकरी से मिले सांसद डॉ रावत, बांसवाड़ा वाया सलूंबर राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। सांसद मन्नालाल रावत ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर आदिवासी क्षेत्र में बांसवाड़ा वाया सलूंबर राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने तथा उदयपुर से प्रतापगढ़, जावरा वाया बांसी, धरियावद को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने तथा उदयपुर से झाडोल मार्ग पर रण घाटी एवं पालियाखेडा से पूर्व घाट सेक्शन में बाधित निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने सहित अन्य मांगों को लेकर पत्र दिया। श्री गडकरी ने जांच एवं समस्या समाधान के लिए सकारात्मक निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। सांसद डॉ रावत ने श्री गडकरी को अवगत कराया गया है कि उदयपुर से बांसवाड़ा वाया सलूम्बर स्टेट हाईवे (एसएच 32) संकीर्ण होकर जाम से ग्रस्त रहता है, जिससे प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं होती है। इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर चार लेन मार्ग में परिवर्तित करने से समस्या का समाधान हो सकता है। यह मार्ग उदयपुर संभाग मुख्यालय से जिला सलूम्बर से होकर बांसवाड़ा जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 156.50 किमी है। इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने पर मेवाड एवं वागड क्षेत्र जो मुख्यतः आदिवासी क्षेत्र है, की जनता को कई लाभ होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से भविष्य में मेवाड़ एवं वागड़ क्षेत्र की जनता को मध्यप्रदेश (रतलाम) एवं गुजरात (दाहोद) जाने हेतु सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी। इस मार्ग पर सुगम, सुरक्षित व त्वरित सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्राप्त होगी। इस आदिवासी क्षेत्र में विविध कृषि, वन, औद्योगिक उत्पादन की संभावनाएं बनेगी, जिससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इस सडक पर वर्तमान में दुर्घटनाएं होने के कारण इस क्षेत्र की जनता को दिन-प्रतिदिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग बनने के पश्चात् दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसी तरह सांसद डॉ रावत ने उज्जैन महानगरी को उदयपुर तक जोड़ने के लिए उदयपुर से जावरा वाया बान्सी, धरियावद, प्रतापगढ़ एक्सप्रेसवे सड़क की स्वीकृति का आग्रह किया है। पत्र में बताया कि उज्जैन (म०प्र०) से उदयपुर (राज०) की दूरी लगभग 375 कि.मी. है, जिसको पार करने के लिए वर्तमान में 6-8 घंटे का समय लगता है। जानकारी में आया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन से जावरा तक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, जिससे उज्जैन के लिए 8-लेन एक्सप्रेसवे पर आवागमन सुगम होगा। जावरा से प्रतापगढ़ (राज०) तक 8-लेन एक्सप्रेसवे के सड़क निर्माण के लिए पूर्व में चित्तौड़गढ़ के सांसद सी.पी. जोशी द्वारा भी आग्रह किया गया है। उदयपुर शहर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर है। यह झीलो की नगरी का शहर अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उदयपुर से लगभग 50-60 कि.मी. दूरी पर स्थित श्रीकृष्ण से संबंधित श्रीनाथजी (नाथद्वारा) फोर लेन एवं सांवरिया सेठ (मंडफिया) सिक्स लेन सड़क से जुड़े हुये है। उदयपुर शहर से बान्सी, धरियावद, प्रतापगढ़ होते हुये जावरा तक एक्सप्रेसवे बनाने से न सिर्फ धार्मिक आवागमन सुगम एवं द्रुतगति से संभव होगा अपितु, दिल्ली-मुम्बई 8 लेन एक्सप्रेसवे से जुड़ने से उदयपुर, प्रतापगढ़, धरियावद, सलुम्बर आदि जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों का शैक्षणिक एवं औद्योगिक उत्थान में भी वृद्धि होगी। साथ ही उदयपुर से जावरा की दूरी घटकर लगभग 160 कि.मी. की हो जायेगी जिससे कि यातायात का समय 6 घंटे से घटकर लगभग 2 घंटे रह जायेगा। सांसद डॉ रावत ने दक्षिण राजस्थान के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के बहुमुखी विकास एवं क्षेत्रवासियों की मांग को देखते हुए उदयपुर से दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस-वे के जावरा बिन्दु तक (उदयपुर-बान्सी धरियावद प्रतापगढ़-जावरा) एक्सप्रेसवे सड़क की स्वीकृति जल्द प्रदान करवाने का आग्रह किया।

अवैध अंग्रेजी शराब की विभिन्न ब्राण्ड की 17 बोतलें जब्त

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के सुपरविजन में गिर्वा वृताधिकारी सूर्यवीर सिंह राठौड़ एवं गोवर्धन विलास थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला के नेतृत्व में जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के लेक गार्डन कॉम्प्लेक्स स्थित एक फ्लैट से हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की 17 बोतलें जब्त की हैं। 14 अप्रैल को जिला स्पेशल टीम प्रभारी पुलिस निरीक्षक श्याम सिंह की सूचना पर गोवर्धन विलास थाना पुलिस टीम ने फ्लैट नंबर बी-103, लेक गार्डन में दबिश दी। तलाशी के दौरान फ्लैट की बालकनी में रखे प्लास्टिक के कट्टे में 17 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई, जिन पर हरियाणा निर्मित ब्रांड के फर्जी स्टीकर लगे थे। शराब पर इस प्रकार स्टीकर लगाए गए थे कि वह राजस्थान में निर्मित प्रतीत हो, ताकि उसे प्रदेश में बेचा जा सके और अवैध मुनाफा कमाया जा सके।

गिरफ्तार आरोपी

पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हर्षा नाचानी, पत्नी निखिल पंजाबी, उम्र 38 वर्ष, निवासी 50 बी, जवाहर नगर, थाना सूरजपोल, चिराग नाचानी, पुत्र स्व. गोपालदास नाचानी, निवासी फ्लैट नंबर बी-103, लेक गार्डन कॉम्प्लेक्स, थाना गोवर्धन विलास। इन पर धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम और धारा 340(2), 341(3) बीएनएस के तहत प्रकरण संख्या 146/25 दर्ज कर आगे अनुसंधान जारी है।

पुलिस टीम में शामिल अधिकारी

जिला स्पेशल टीम की अहम भूमिका रही। टीम में शामिल अधिकारी- श्याम सिंह, पुलिस निरीक्षक (डीएसटी प्रभारी), विक्रम सिंह, सहायक उपनिरीक्षक, हितेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल, भंवर विश्नोई, हेड कांस्टेबल, जगदीश, योगेश, गणेश सिंह, करतार सिंह, सुमेर सिंह (हेड कांस्टेबल डीएसटी), जितेन्द्र, मुकेश, शक्ति सिंह, सुमित, कमलेश (कांस्टेबल), मैना (महिला कांस्टेबल),

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा ।